जी. एम. शाह

बनाम

जम्मू और कश्मीर राज्य

30 अक्टूबर, 1979

[वी.डी. तुलजापुरकर और ई. एस. वेंकटरमैया, जे.जे.]

जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 की धारा 8(2) और 8(3) दायरा - "कानून और व्यवस्था", "सार्वजनिक व्यवस्था", "राज्य की सुरक्षा" - तात्पर्य।

याचिकाकर्ता के बेटे (निरुद्ध) को जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 की धारा 8(2) के तहत जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग के एक आदेश द्वारा अभिरक्षा में लिया गया था, अधिनियम की धारा 8(1)(ए)(1) और 8(2) 2 में कहा गया है कि सरकार या जिला मजिस्ट्रेट, दि किसी व्यक्ति के संबंध में यह संतुष्ट है कि उसे राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से, ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने का निर्देश देने वाला आदेश दें।

निरुद्ध व्यक्ति को सूचित किया गया कि अभिरक्षा का आदेश उसे "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव" के लिए हानिकारक किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से पारित किया गया था। अन्य बातों के

अलावा हिरासत के आधारों में कहा गया है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति (i) विध्वंसक गतिविधियों में शामिल था (ii) राज्य में अराजकता पैदा करने के लिए धार्मिक स्थलों को जलाने का आयोजन किया गया (iii) सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ दिया (iv) मौत की सजा पाए व्यक्ति के पक्ष में जनता की राय जानने की कोशिश की और उसका फरार रहना सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव और "राज्य की सुरक्षा" के लिए हानिकारक था।

याचिकाकर्ता ने नजरबंदी के आधार को अस्पष्ट बताते हुए चुनौती दी।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को अनुमति देते हुए और निरुद्ध व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का निर्देश देते हुए-

अभिनिर्धारित किया : किसी भी नागरिक की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जनमत प्राप्त करने और उसे फांसी से बचाने के प्रयास को राज्य की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे राज्य में कानून द्वारा स्थापित सरकार को उखाड़ फेंकने या भयभीत करने के प्रयास के रूप में नहीं माना जा सकता है। तथ्य यह है कि बंदी ने जेडए भुट्टो की प्रस्तावित फांसी के खिलाफ लोगों की भावनाओं को जगाने के लिए हैंड-बिल और पुस्तिकाएं भेजी थीं, इसे राज्य की सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि

जम्मू-कश्मीर राज्य का प्रस्तावित निष्पादन से कोई लेना-देना नहीं था। जहां तक राज्य की सुरक्षा का प्रश्न है, अन्य आधार भी अस्पष्ट हैं। [1111 बी-ई]

हिरासत के आदेश और बंदी को दिए गए आधारों को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि जिस समय आदेश दिया गया था, उस समय जिला मजिस्ट्रेट के पास राज्य की सुरक्षा से संबंधित कोई सामग्री नहीं थी, जिस पर वह कार्रवाई कर सके या यदि उसके पास थी भी तो उन आधारों की जानकारी के बावजूद, उन्होंने उस पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं दिया। हालाँकि, उन्होंने यह कहकर हिरासत के आदेश का समर्थन करने की कोशिश की कि हिरासत में लिए गए लोगों के बड़े पैमाने पर रहने से राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। [1111 जी-एच]

अभिव्यक्ति "कानून और व्यवस्था", "सार्वजनिक व्यवस्था" और "राज्य की सुरक्षा" अलग-अलग अवधारणाएँ हैं, हालांकि अब हमेशा अलग हैं। जबकि शांति का प्रत्येक उल्लंघन कानून और व्यवस्था को बाधित करने के बराबर हो सकता है, इस तरह का प्रत्येक उल्लंघन सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के बराबर नहीं है और प्रत्येक सार्वजनिक व्यवस्था "राज्य की सुरक्षा" को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं कर सकती है। [ 1112 ए-बी]

रोमेश थाप्पर बनाम मद्रास राज्य, [1950] एस.सी.आर. 594 पी.600 लागु किया।

एक अधिनियम कानून और व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को नहीं, क्योंकि एक अधिनियम सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, लेकिन राज्य की सुरक्षा को नहीं। यही कारण है कि अधिनियम "राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करना" और "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करना" अभिव्यक्तियों को अलग-अलग परिभाषित करता है। निरोध का आदेश या तो इस आधार पर दिया जाता है कि निरोध में लेने वाले प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश दिया जा रहा है वह राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक किसी भी तरीके से कार्य कर रहा है या इस आधार पर कि वह संतुष्ट है कि ऐसा व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य कर रहा है, लेकिन निरुद्ध को दिए गए दोनों आधारों पर भरोसा करके समर्थित होने के प्रयास को अवैध माना जाना चाहिए। [1113 सी-डी]

डॉ. राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य और अन्य, [1966] 1 एस. सी. आर. 709। भूपाल चंद्र घोष बनाम। आरिफ अली और अन्य

[1974] 2 एस. सी. आर. 277 और सत्य ब्रता घोष बनाम आरिफ अली और अन्य ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 258 अनुसरण किया गया।

मूल क्षेत्राधिकार : रिट याचिका संख्या 1125/1979

(संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

एम. के. राममूर्ति और आर. सी. पाठक, याचिकाकर्ता की ओर से।

के. के. वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और अल्ताफ अहमद, प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया -

वेंकटरमैया, न्यायाधिपति.- उपरोक्त याचिका पर सुनवाई के समापन पर 24 अक्टूबर, 1979 को हमने निम्नलिखित आदेश दियाः

> "शब्बीर अहमद शाह, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट, अनंतनाग के 23 मई, 1979 के आदेश द्वारा हिरासत में लिया गया था, को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। कारण अनुसरण करेंगे।"

उपरोक्त आदेश के समर्थन में कारण नीचे दिए गए हैंः-

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उपरोक्त याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें इस न्यायालय से जम्मू और कश्मीर राज्य

में जिला मजिस्ट्रेट, अनंतनाग द्वारा पारित हिरासत संख्या 299-304/ST दिनांक 23 मई, 1979 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 (1978 का अधिनियम संख्या VI) (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 8(2) के तहत उनके (याचिकाकर्ता के) बेटे, शब्बीर अहमद शाह (इसके बाद संदर्भित) को हिरासत में लेने का निर्देश दिया गया है। 'हिरासत' के रूप में)। हिरासत के आदेश का प्रासंगिक भाग पढ़ता है:

> "जबकि मैं, उमर जान, जिला मजिस्ट्रेट, अनंतनाग, संतुष्ट हूं कि श्री शब्बीर अहमद शाह पुत्र गुलाम मोहम्मद शाह निवासी कदीपोरा, अनंतनाग को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है;
>
> अब, इसलिए, जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 (अधिनियम सं. VI ऑफ़ 1978) की धारा 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, उमर जान, जिला मजिस्ट्रेट, अनंतनाग एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि उक्त श्री शब्बीर अहमद शाह को श्रीनगर की केंद्रीय जेल में निरुद्ध रखा जाए।
>
> एसडी/-

(उमर जान)

जिला मजिस्ट्रेट

अनंतनाग। ”

बंदी को अधिनियम की धारा 13 के अनुसरण में सूचित किया गया था निम्नलिखित आधारों पर नजरबंदी का आदेश दिया गया थाः

"1. आप मूल रूप से यंग मैन लीग (हामिद समूह) से संबंधित थे जो युवाओं का एक राष्ट्र-विरोधी और पाकिस्तान समर्थक संगठन था। आप अपने पूर्व सहयोगियों के साथ राष्ट्र-विरोधी प्रदर्शनों और विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करके सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव में तोड़फोड़ और खतरा पैदा करने के लिए जिम्मेदार थे।

2. बाद में वर्ष 1975 में जब राज्य के भारत में विलय को चुनौती देने और राज्य में पाकिस्तान के हितों को आगे बढ़ाने के घोषित उद्देश्य के साथ पीपुल्स लीग का गठन किया गया, तो आप एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी में शामिल हो गए। आप वर्तमान में पीपुल्स लीग के महासचिव हैं। आपने और आपकी पार्टी ने खुली सहानुभूति दिखाई है और मोहम्मद मकबूल भट के पक्ष में जनता की राय जुटाने की कोशिश की है, जो एक कट्टर पाकिस्तान समर्थक

विध्वंसक तत्व है, जिसे हत्या, जासूसी और तोड़फोड़ के लिए दो मौकों पर मौत की सजा सुनाई गई है और वर्तमान में इसके निष्पादन की प्रतीक्षा में है। पीपुल्स लीग की ओर से मोहम्मद मकबूल भट के समर्थन में पर्चे और पोस्टर जारी किए गए हैं।

3. जनवरी और फरवरी, 1970 में आप सोपोर क्षेत्र के विध्वंसक तत्वों में शामिल हो गए और राज्य में अराजकता पैदा करने के लिए धार्मिक स्थलों को जलाने का आयोजन किया। हालाँकि, ज्यादा नुकसान होने से पहले ही बारामूला पुलिस ने समय रहते इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। आपको इस संबंध में दर्ज केस एफआईआर नंबर 38/79 धारा 436 आईपीसी पीएस सोपोर में गिरफ्तार किया गया था।

4. पाकिस्तान में श्री जेड.ए. भुट्टो की फांसी से बहुत पहले, आपने और आपकी पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ लोगों की भावनाओं को जगाने के लिए हैंड-बिल और पुस्तिकाएं भेजी थीं। आप अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ घाटी में असंतुष्ट और अवांछनीय तत्वों के साथ संपर्क बनाए रखने और इस संबंध और संदर्भ में उनकी आधार भावनाओं को जगाने के लिए गुप्त रूप से चले गए।

5. मार्च, 1979 के तीसरे सप्ताह में, जब कुछ बेरोजगार युवाओं ने लाल चौक, अनंतनाग में भूख हड़ताल शुरू की, तो आपने सीपीआई एमएल और अन्य दलों को समर्थन दिया जो अशांति पैदा करने और युवाओं को हिंसा और विकार के लिए उकसाने के लिए तैयार थे।

6. 29-3-1979 को आपने अपने सहयोगियों के साथ एक बैठक की और अगले दिन भुट्टो समर्थक भावनाओं और प्रदर्शनों के संदर्भ में अनंतनाग शहर में सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने का निर्णय लिया।

7. परिणामस्वरूप 30-3-1979 को आप अपने सहयोगियों के साथ चुपचाप दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करने की चेतावनी देने चले गये। आपने लोगों को सड़क जाम करने और ट्रैफिक जाम करने के लिए भी उकसाया. आपने और आपके सहयोगियों ने अनंतनाग कॉलेज में हड़ताल का आयोजन किया; जब यह 30 तारीख को खुला। बाद में आपने अपने सहयोगियों के साथ युवाओं को हिंसा करने और अव्यवस्था पैदा करने के लिए उकसाया। परिणामस्वरूप अनंतनाग शहर में पुलिस और मजिस्ट्रेट पर जानलेवा हमले सहित बहुत सारी हिंसा हुई जिसमें कई

अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। धारा 302/148/336/332/1491120-बी आईरपीसी के तहत मामला एफआईआर नंबर 98/i9 दर्ज किया गया था। आप भूमिगत हो गए और काफी समय तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके लेकिन बाद में आपको मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में आप फिलहाल जमानत पर हैं। 7-4-1979 को जब अनंतनाग शहर में सामान्य स्थिति बहाल हो रही थी और दुकानें खोली जा रही थीं, आप अपने सहयोगियों के साथ लाल चौक के पास आये और दुकानदारों को दुकानें बंद करने की धमकी दी। उनके चिल्लाने और भागने से कस्बे में तनाव पैदा हो गया और कई दुकानें बंद हो गईं। आपको गिरफ्तार करने के पुलिस प्रयास सफल नहीं हो सके क्योंकि आप गलियों में भाग गये और बाद में भूमिगत हो गये।

8. हाल ही में आप राष्ट्र विरोधी, पाकिस्तान समर्थक तत्वों के साथ सहयोग कर रहे हैं जो आपके साथ गुप्त बातचीत और संबंध बनाने आते हैं। आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अराजकता, अव्यवस्था, विध्वंस और इस तरह की चीजें पैदा करने के लिए प्रयास करने वाले एक खतरनाक और नीच चरित्र हैं। आपका बड़े पैमाने पर रहना

सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव और राज्य की सुरक्षा के लिए भी प्रतिकूल है। मुझे विश्वास है कि जब तक आपको हिरासत में नहीं लिया जाता, इस बात की पूरी संभावना है कि आप जनता के मन में भ्रम पैदा करते रहेंगे और लोगों को अराजकता और सार्वजनिक शांति में अशांति के लिए उकसाते रहेंगे।

(पैराग्राफ को हमारे द्वारा सुविधा के उद्देश्य से क्रमांकित किया जाता है।)

यह ध्यान दिया जा सकता है कि निरोध के आदेश में कहा गया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकने" की दृष्टि से पारित किया गया था, वहीँ हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दिए गए आधार के पैराग्राफ के अनुसार, यह कहा गया था कि "आपका बड़े पैमाने पर रहना राज्य के रखरखाव और राज्य की सुरक्षा के लिए भी प्रतिकूल है"। अधिनियम की धारा 8 जिसके तहत निरोध का आदेश दिया गया है, सुसंगत भाग इस प्रकार है:

"8. कुछ व्यक्तियों की हिरासत - (1) सरकार -

ए) यदि किसी व्यक्ति के संबंध में इस बात से संतुष्ट हैं कि उसे किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से -

(i) राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव, या

(ii) समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव; या

(बी) ऐसा आदेश देना देना आवश्यक है, जिसमें निर्देश दिया जाए कि ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिया जाए।

(2) (2) निम्नलिखित अधिकारियों में से कोई भी अर्थात्:- (i) संभागीय आयुक्त, (ii) जिला मजिस्ट्रेट, उप-धारा (1) के खंड (ए) के उप-खंड (i) और (ii) में दिए गए अनुसार संतुष्ट होने पर, उक्त उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

(3) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए -

(ए) "किसी भी तरीके से राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल कार्य करना" का अर्थ है उपयोग करने, या उपयोग करने का प्रयास, या उपयोग करने या उकसाने, उकसाने, उकसाने की

तैयारी करना या अन्यथा राज्य में कानून द्वारा स्थापित सरकार को उखाड़ फेंकने या भयभीत करने के लिए बल प्रयोग को बढ़ावा देना;

(बी) "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करना" का अर्थ है-

(i) धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावनाओं को बढ़ावा देना, प्रचारित करना या पैदा करने का प्रयास करना;

(ii) बल प्रयोग का उपयोग करने, या उपयोग करने का प्रयास, या उपयोग करने, या उकसाने, भड़काने, उकसाने, अन्यथा उकसाने के लिए तैयारी करना जहां ऐसी तैयारी, उपयोग, प्रयास, उकसाना, उकसाना, उकसाना या उकसाना, परेशान करना या करने की संभावना है सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डालना;

(iii) रणबीर दंड संहिता की धारा 425 के अर्थ के अंतर्गत शरारत करने का प्रयास करना, या करना, या उकसाना, भड़काना, भड़काना या अन्यथा ऐसा करने के लिए उकसाना,

जहां ऐसी शरारत करने से सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी होती है, या गड़बड़ी होने की संभावना है;

(iv) प्रतिबद्ध होने का प्रयास करना, या प्रतिबद्ध होना। या मौत या आजीवन कारावास या सात साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध को करने के लिए उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना या अन्यथा उकसाना, जहां ऐसे अपराध का कमीशन सार्वजनिक व्यवस्था को परेशान करता है, या परेशान करने की संभावना है।"

ऊपर निकाले गए अधिनियम की धारा 8(1)(ए)(आई) और धारा 8(2) से पता चलता है कि सरकार या जिला मजिस्ट्रेट, यदि किसी व्यक्ति के संबंध में संतुष्ट हैं, तो उसे राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से, ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने का निर्देश देने वाला आदेश दे सकता है। अभिव्यक्ति "किसी भी तरीके से कार्य करना पूर्व।" राज्य की सुरक्षा के लिए न्यायिक" अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के खंड (ए) में राज्य में कानून द्वारा स्थापित सरकार को उखाड़ फेंकने या भयभीत करने के लिए बल का उपयोग करने, या उपयोग करने का प्रयास करने, या उपयोग करने या उकसाने, भड़काने, उकसाने या अन्यथा उकसाने की तैयारी के रूप में, परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 8(3) का खंड (बी)

"सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करना" अभिव्यक्ति को परिभाषित करता है। दोनों अभिव्यक्तियों के बीच अंतर इस तथ्य में निहित है कि पूर्व के मामले में, तैयारी करने या बल प्रयोग आदि के लिए उकसाने या बढ़ावा देने का उद्देश्य "राज्य में कानून द्वारा स्थापित सरकार" को उखाड़ फेंकने या भयभीत करने की दृष्टि से होना चाहिए। उत्तरार्द्ध के मामले में, उसमें उल्लिखित कृत्यों का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी होना चाहिए।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, जबकि हिरासत के आदेश में कहा गया है कि यह बंदी को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से किया जा रहा था, उसे बताए गए आधार में, यह कहा गया था कि बंदी का बाहर रहना सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव और राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल था। अब हम संक्षेप में बंदी को दिए गए आधार की प्रकृति का उल्लेख करेंगे। सबसे पहले हम आधारों के पैराग्राफ (1), (3) और (5) से (7) पर विचार करेंगे। आधार के पैराग्राफ (1) में, यह कहा गया है कि बंदी अपने पूर्व सहयोगियों के साथ राष्ट्र-विरोधी प्रदर्शनों और विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करके सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव में तोड़फोड़ और खतरा पैदा करने के लिए जिम्मेदार था। आधार के पैराग्राफ (3) में, ऐसा कहा जाता है कि जनवरी और फरवरी, 1979 में, बंदी सोपोर क्षेत्र के विध्वंसक

तत्वों में शामिल हो गए थे और राज्य में अराजकता पैदा करने के लिए धार्मिक स्थलों को जलाने का आयोजन किया था। आधार के पैराग्राफ (5) में, ऐसा कहा जाता है कि मार्च 1979 के तीसरे सप्ताह में, बंदी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एमएल) और अन्य दलों को समर्थन दिया था जो गड़बड़ी पैदा करने और युवाओं को हिंसा और अव्यवस्था के लिए उकसाने के लिए उकसा रहे थे जब कुछ बेरोजगार हो गए थे। अनंतनाग के लाल चौक पर युवाओं ने शुरू की भूख हड़ताल. आधार के पैराग्राफ (6) में, ऐसा कहा जाता है कि 29 मार्च, 1979 को बंदी ने अपने सहयोगियों के साथ एक बैठक की और अनंतनाग शहर में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने का फैसला किया। आधार के पैराग्राफ (7) में, इसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति और उसके साथियों द्वारा युवाओं को हिंसा करने और अव्यवस्था पैदा करने के लिए उकसाने का जिक्र है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पैराग्राफ (1), (3) और (5) से (7) के आधार पर, कानून द्वारा स्थापित सरकार को उखाड़ फेंकने या भयभीत करने के लिए बंदी द्वारा बल प्रयोग करने के किसी भी प्रयास का कोई प्रतिकार नहीं है। राज्य। आधार के पैराग्राफ (2), (4) और (8) भी किसी भी तरह से भिन्न नहीं हैं। आधार के पैराग्राफ (2) में, हालांकि हिरासत में लिए गए लोगों के पीपुल्स लीग में शामिल होने का संदर्भ है, जिसका गठन जम्मू और कश्मीर राज्य के भारत में विलय को चुनौती देने और कारण और हित को आगे बढ़ाने के एक घोषित उद्देश्य के साथ किया गया था। राज्य में पाकिस्तान के, हिरासत में लिए गए कृत्य के लिए जिम्मेदार यह

है कि उसने मोहम्मद मकबूल भट के पक्ष में जनता की राय जानने की कोशिश की थी, जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी। किसी भी नागरिक की ओर से मौत की सजा पाए किसी व्यक्ति के पक्ष में जनता की राय जानने और उसे फांसी से बचाने के प्रयास को राज्य की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य नहीं माना जा सकता है। क्योंकि इसे राज्य में कानून द्वारा स्थापित सरकार को उखाड़ फेंकने या उसे खत्म करने का प्रयास नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार, आधार के पैराग्राफ (4) में बंदी को दिए गए कृत्य को राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक कृत्य नहीं माना जा सकता क्योंकि उसमें जो आरोप लगाया गया है वह यह है कि पाकिस्तान में श्री जेड.ए. भुट्टो की फांसी से बहुत पहले, बंदी ने ऐसा किया था। लोगों की भावनाएँ जागृत करने के लिए हैण्ड-बिल और पुस्तिकाएँ भेजीं। यद्यपि यह कहा गया है कि बंदी ने राज्य सरकार के खिलाफ लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की थी, बंदी की ओर से कथित कृत्य भले ही सच हो, इसे जम्मू राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक नहीं माना जा सकता है। और कश्मीर क्योंकि जम्मू और कश्मीर राज्य का श्री जेड.ए.भुट्टो की प्रस्तावित फांसी से कोई लेना-देना नहीं था। ग्राउंड नंबर 8 जिसमें भौतिक विवरणों का अभाव है, सामान्य प्रतीत होता है। जहां तक राज्य की सुरक्षा का प्रश्न है, ये आधार भी अस्पष्ट हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बंदी को प्रदान किया गया कोई भी आधार अधिनियम की धारा 8(3)(1) के खंड (ए) के दायरे में नहीं आता है जो अभिव्यक्ति “किसी भी तरह से राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल कार्य करना" को परिभाषित करता है। आगे यह देखा गया है कि भले ही इस आधार पर कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट का विचार था कि हिरासत में लिए गए लोगों का बड़े पैमाने पर रहना राज्य की सुरक्षा के लिए भी हानिकारक था, उन्होंने राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से यह आदेश नहीं दिया। हिरासत के आदेश और बंदी को दिए गए आधारों को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि जिस समय आदेश दिया गया था, उस समय जिला मजिस्ट्रेट के पास राज्य की सुरक्षा से संबंधित कोई सामग्री नहीं थी, जिस पर वह कार्रवाई कर सके या यदि उसके पास थी भी तो उन आधारों की जानकारी के बावजूद, उन्होंने उस पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं दिया। हालाँकि, उन्होंने इस आधार पर यह कहकर हिरासत के आदेश का समर्थन करने की कोशिश की कि हिरासत में लिए गए लोगों के बड़े पैमाने पर रहने से राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अभिव्यक्तियाँ "कानून और व्यवस्था", "सार्वजनिक व्यवस्था" और "राज्य की सुरक्षा" अलग-अलग अवधारणाएँ हैं, हालाँकि हमेशा अलग नहीं होती हैं। जबकि शांति का प्रत्येक उल्लंघन कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी

के समान हो सकता है, ऐसा प्रत्येक उल्लंघन सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी की श्रेणी में नहीं आता है और प्रत्येक सार्वजनिक अव्यवस्था "राज्य की सुरक्षा" पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकती है। यह बात रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य [(1)] मामले में इस न्यायालय के फैसले में पतंजलि शास्त्री, जे. द्वारा की गई टिप्पणियों से सामने आती है, जो इस प्रकार हैं: -

> "जैसा कि स्टीफ़न ने अपने क्रिमिनल लॉ ऑफ़ इंग्लैंड में कहा है: गैरकानूनी सभाएं, दंगे, विद्रोह, विद्रोह, युद्ध थोपना, ऐसे अपराध हैं जो एक-दूसरे से टकराते हैं और पूरी तरह से परिभाषित सीमाओं से चिह्नित होने में सक्षम नहीं हैं। उन सभी में एक समान विशेषता है, अर्थात् सभ्य समाज की सामान्य शांति उल्लिखित प्रत्येक मामले में या तो वास्तविक बल से या कम से कम उसके प्रदर्शन और धमकी से परेशान होती है। यद्यपि इन सभी अपराधों में सार्वजनिक शांति की गड़बड़ी शामिल है और सैद्धांतिक रूप से सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ अपराध हैं, उनके बीच का अंतर केवल डिग्री का अंतर है, फिर भी उनके संबंध में दी जाने वाली सजा को वर्गीकृत करने के उद्देश्य से उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है विभिन्न छोटी श्रेणियाँ जैसा कि भारतीय दंड संहिता द्वारा किया गया है। इसी प्रकार,

संविधान ने अनुच्छेद 19(1) में उल्लिखित मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाले अनुमेय कानून के लिए अलग-अलग मानदंड तैयार करते हुए, सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ उन अपराधों को एक अलग श्रेणी में रखा है, जिनका उद्देश्य राज्य की सुरक्षा को कमजोर करना या उसे उखाड़ फेंकना है। , और उनकी रोकथाम को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विधायी हनन का एकमात्र औचित्य बना दिया, कहने का तात्पर्य यह है कि, राज्य की नींव को खतरे में डालने या इसे उखाड़ फेंकने की धमकी देने से कम कुछ भी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों में कटौती को उचित नहीं ठहरा सकता है, जबकि शांतिपूर्ण सभा का अधिकार "उपखंड (बी)" और संघ का अधिकार "उपखंड (सी)" को "सार्वजनिक व्यवस्था" के हित में अनुच्छेद 19 के खंड (3) और (4) के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है। " जिसमें, उन धाराओं में राज्य की सुरक्षा शामिल है। यह अंतर सातवीं अनुसूची की सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 3 में भी ध्यान देने योग्य है, जो "राज्य की सुरक्षा" और "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव" को कानून के अलग-अलग विषयों के रूप में संदर्भित करता है। इस प्रकार संविधान को सार्वजनिक व्यवस्था या शांति के

क्षेत्र में एक रेखा खींचने की आवश्यकता है, जो मोटे तौर पर सार्वजनिक अव्यवस्था के उन गंभीर और गंभीर रूपों के बीच की सीमा हो सकती है, जो राज्य की सुरक्षा और अपेक्षाकृत छोटे को खतरे में डालती है। विशुद्ध रूप से स्थानीय महत्व की शांति का उल्लंघन, इस उद्देश्य के लिए डिग्री में मतभेदों को इस तरह मानना जैसे कि वे प्रकार में मतभेद थे।"

जैसा कि हिदायतुल्ला, जे. (जैसा कि वे उस समय थे) ने डॉ. राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य और अन्य [(1)] में माना था, उपरोक्त अभिव्यक्तियों के अर्थ और अर्थ को समझने के लिए, तीन संकेंद्रित वृत्तों की कल्पना करनी होगी। 'कानून और व्यवस्था' सबसे बड़े वृत्त का प्रतिनिधित्व करता है जिसके भीतर अगला वृत्त "सार्वजनिक व्यवस्था" का प्रतिनिधित्व करता है और सबसे छोटा वृत्त "राज्य की सुरक्षा" का प्रतिनिधित्व करता है। यह देखना आसान है कि एक अधिनियम कानून और व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को नहीं, जैसे एक अधिनियम सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, लेकिन राज्य की सुरक्षा को नहीं। उपरोक्त अंतर को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम "राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक किसी भी तरीके से कार्य करना" और "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी

तरीके से कार्य करना" को अलग-अलग परिभाषित करता है। हिरासत का आदेश या तो इस आधार पर दिया जाता है कि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी संतुष्ट है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश दिया जा रहा है वह राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक किसी भी तरीके से कार्य कर रहा है या इस आधार पर कि वह संतुष्ट है कि ऐसा व्यक्ति कार्य कर रहा है किसी भी तरह से सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल, लेकिन जिसे हिरासत में लिए गए आधारों में दोनों आधारों पर निर्भरता रखकर समर्थन करने का प्रयास किया गया है, उसे भूपाल चंद्र घोष बनाम आरिफ़ अली और अन्य [(2)] तथा सत्य ब्रता घोष बनाम आरिफ़ अली और अन्य [(3)] में इस न्यायालय के फैसले के तहत अवैध माना जाएगा।

अतः निरोध का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है और निरोधी को रिहा किए जाने का अधिकार है। याचिका तदनुसार स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, हमने श्री एम.के.राममूर्ति द्वारा दिए गए अन्य तर्क पर ध्यान नहीं दिया है कि हिरासत में लिए गए कई आधार अस्पष्ट हैं, हिरासत के आदेश का इस आधार पर भी समर्थन नहीं किया जा सकता है कि इसे बंदी को सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करने से रोकने की दृष्टि से पारित किया गया था।

एन.के.ए.

याचिका स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

**<u>अस्वीकरण</u>**- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****